

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,

उत्तराखण्ड, काशीपुर।

सहकारिता गन्ना एवं चीनी अनुभाग-2

देहरादून

दिनांक 16 जनवरी, 2009

विषय- उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में राज्य की सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों को पेराई सत्र 2007-08 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु रुपये 14,16,00,000 (चौदह करोड़ सोलह लाख रु० मात्र) की अधिकतम सीमा तक ऋण के रूप में दिये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति पेराई सत्र 2007-08 के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु पूर्व में शासनादेश संख्या-520/2008/XIV-2/10/07, दिनांक 07.10.2008 द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृत धनराशि रु० 42.13 करोड़ के क्रम में प्रदान की जा रही है। पेराई सत्र 2007-08 के लिए गन्ना कृषकों को अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु सहकारी तथा निगम क्षेत्र की चीनी मिलों को आपके स्तर से ऋण प्रदान किये जाते समय शासनादेश संख्या-17/2008/XIV-2/28/2008, दिनांक 23.01.2008 तथा मा० उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान संबंधी याचिकाओं में पारित किये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पुनः यह भी कि यह प्रक्रिया/कार्यवाही सन्दर्भगत याचिकाओं में मा० न्यायालय के अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन होगी।

3. उक्त ऋण का उपयोग केवल गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ही किया जायेगा तथा सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों को धनराशि तत्काल प्रदान करा दी जायेगी। संबंधित प्रधान प्रबंधक/अधिशाली निदेशक, चीनी मिल यह सुनिश्चित करेंगे कि इस धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य मद में न किया जाए। व्यावर्तन की स्थिति में संबंधित प्रधान प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4. उक्त ऋण पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, जिसकी ब्याज सहित अदायगी आगामी पाँच वर्षों में वार्षिक किश्तों में की जायेगी। ब्याज सहित प्रथम किश्त की अदायगी 01.04.2009 तक देय होगी।

5. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार (लेखा) कार्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखाशीर्षक, सूचित करते हुए भेजेंगे।

6. सहकारी तथा निगम क्षेत्र की चीनी मिलें जब भी किश्तों का भुगतान करें या ब्याज जमा करें, यह महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजेंगे:-

- (1) कोषागार का नाम
- (2) चालान संख्या तथा दिनांक
- (3) जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज
- (4) लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया
- (5) शासनादेश संख्या और एव0एल0आर0 का संदर्भ
- (6) पिछले जमा का संदर्भ

सहकारी तथा निगम क्षेत्र की चीनी मिलें, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड आहरण के प्रत्येक वर्ष अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करावें।

7. भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि निगम/सहकारी चीनी मिलों ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाणपत्र अवश्य उपलब्ध करा दें।

8. इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जायेगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाणपत्र भी अनिवार्यतः शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

9. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाये।

10. यह गन्ना एवं चीनी आयुक्त तथा उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 का संयुक्त उत्तरदायित्व होगा कि वे चीनी मिलों के वित्तीय घाटे को न्यूनतम/समाप्त करने तथा चीनी मिलों के लाभकारी संचालन हेतु दो माह के भीतर सुधारात्मक कार्य योजना तैयार करते हुए अगले पेरार्ड सत्र से पूर्व उसका कियान्वयन सुनिश्चित कर लें, तथा सुधारात्मक परिणामों से शासन को अवगत करावें।

11. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-17 के लेखाशीर्षक 6401-फसल कृषि कर्म के लिये कर्ज, 109-वाणिज्यिक फसलें, 10-उत्तराखण्ड सहकारी क्षेत्र/निगम की मिलों को ऋण, 30-निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के आदेशपत्र संख्या-142 (NP)/XXVII-04/08, दिनांक 15.01.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजीव चन्द्र)  
सचिव।

संख्या-34 (1)/2009/XIV-2/10/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी/क्रोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि०, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग 1 एवं 4/बजट निदेशालय/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा० गन्ना मंत्री जी को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
5. सहायक गन्ना आयुक्त, ऊधमसिंहनगर/देहरादून/हरिद्वार।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

16.1.09  
(विनोद शर्मा)  
अपर सचिव।